by not only tariff and non-tariff barriers but also by the massive export subsidies granted by the USA, EEC, etc. Lack of infrastructural facilities (like air cargo facilities not keeping pace inadequate shipping/cold storage facilities), high air freight rates, stringent sanitary and quality standards, and lack of vapour heat treatment facilities are the major constraints hampering export of agricultural commodities.

The removal of non-tariff barriers and reduction of subsidies in the industrialised countries under the WTO Agreement are expected to open up new market opportunities for countries like India.

Under a scheme for Development of Infrastructure, the Government is providing financial assistance to eligible exporters for (i) purchase of specialised transport units, (ii) establishment of pre-cooling facilities, (iii) setting up of mechanised post-harvest handling facilities and sheds for grading, sorting, quality control and packaging, (iv) establishing vapour heat treatment/fumigation screening machines for, exports; and (v) establishing cold stores at airports/seaports for export purposes.

Apart from the general trade policy reforms, other measures taken to increase exports include augmentation of domestic production, market development campaigns abroad and intensification of product development efforts in the country.

धसकने वाली कोयला खानों की पहचान करना

2807. **श्री भगवान मांझी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रानीगंज कोयला क्षेत्र में धसकने वाले क्षेत्रों की पहचान का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रानीगंज कोयला क्षेत्र में पुरानी कोयला खानों को धसकने से रोकने के लिये कोई नई तकनीक विकसित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। रानीगंज कोयला क्षेत्र के 49 धसांव वाले स्थलों की जांच किए जाने हेतु एक शीर्षस्थ निगरानी समिति का गठन किया गया था, जिसमें कोयला कंपनियों, जिला प्रशासन, खान सुरक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय खान अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि तथा सार्वजनिक व्यक्ति (विधान सभा सदस्य, सांसद) आदि शामिल हैं। इस समिति ने यह विचार व्यक्त किए कि 38 स्थल, जो कि 11.8 वर्ग कि०मी० में फैले हुए हैं, वे असुरक्षित हैं।

(ग) और (घ) भूमिगत गढ्ढों को सुदृढ़ीकृत किए जाने हेतु कोई स्थापित प्रौद्योगिकी नहीं है। केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद ने पुराने रानीगंज कोयला क्षेत्र के पहुंचरहित जलमग्न, भूमिगत क्रियाकलापों में जलीय रेत भराई किए जाने के लिए एक माडल अध्ययन किया। दो स्थलों में, इस नयी प्रौद्योगिकी का क्षेत्रीय परीक्षण किया जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी को स्थापित किए जाने हेतु विस्तृत रूप में प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर इस प्रयोजन से दो और स्थलों पर कार्य शुरू किया गया है।

Scheme to Increase Coal Production

2808. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have decided to start a new scheme to motivate employees to increase coal production;

(b) if so, the main features of this scheme;

(c) by when a final dcision in this regard is likely to be taken;

(d) by when this scheme is likely to be implemented; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (e) No new scheme has been decided upon to motivate the employees of Coal India Limited for increasing coal production.